

जेकेलॉन अस्पताल में 500 बैड का अत्याधुनिक आई.पी.डी. टावर का निर्माण करेगी राज्य सरकार

जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में 500 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृहों का निर्माण होगा, मरीजों के परिजनों को सुविधाएं मिलेंगी : खींवसर

जयपुर (कासं)। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत राज्य का वर्ष 2026-27 का बजट स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट में महिला, युवा, गरीब, किसान सहित सभी वर्गों के उत्थान एवं विकसित राजस्थान का दूरदर्शी विजन है। यह बजट आमजन को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मौल का पत्थर साबित होगा।

गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि बजट में वंचित पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविरों का आयोजन



चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर

करने की महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिससे हर परिवार को नि:शुल्क उपचार का लाभ मिल सकेगा। जयपुर स्थित जेके लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता का अत्याधुनिक आईपीडी टावर स्थापित होने से शिशु एवं बाल स्वास्थ्य

■ **प्रदेश में 500 अतिरिक्त इग डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर की स्थापना तथा सड़क दुर्घटना, प्रसूति एवं हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में त्वरित उपचार के लिए राज सुरक्षा योजना लागू करना सराहनीय**

सेवाओं का व्यापक विस्तार होगा। प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा महाविद्यालयों जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर के संबद्ध अस्पतालों में 500 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृहों का निर्माण होने से मरीजों के परिजनों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

खींवसर ने कहा कि प्रदेश में चरणबद्ध रूप से 500 अतिरिक्त इग डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर स्थापित किए जाने की घोषणा से दवा वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और सुलभ बनेगी। सड़क दुर्घटना, प्रसूति एवं हार्ट

अटैक जैसी आपात स्थितियों में त्वरित उपचार सुनिश्चित करने हेतु राज सुरक्षा योजना लागू की जाएगी, जिससे आपातकालीन चिकित्सा तंत्र और अधिक प्रभावी होगा। इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए राज ममता योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।

प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मानसिक स्वास्थ्य केयर सेल भी स्थापित किए जाएंगे। बदलती जीवनशैली एवं बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दौर में मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। अस्पताल परिसरों में स्वच्छ एवं

पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो मरीजों और परिजनों के लिए राहतकारी प्रयास है। इसी प्रकार दुर्घटना में मृत व्यक्ति की पार्थिव देह को सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना शुरू करने की घोषणा संवेदनशील कदम है।

खींवसर ने कहा कि बजट में सड़क, फ्लाईओवर एवं राज् मार्गों के विकास के साथ ही नगरीय निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाने का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन, स्टार्टअप प्रोत्साहन एवं कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार भी बजट की महत्वपूर्ण विशेषता है।

बजट प्रदेश की जनता पर डबल इंजन सरकार का दोहरा कुठाराघात : पायलट



सचिन पायलट

जयपुर (कासं)। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा बुधवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट को निराशाजनक बताया। पायलट ने कहा कि पहले केन्द्रीय बजट में भाजपा सरकार द्वारा राजस्थान की अनदेखी की गई और अब राज्य सरकार ने अपने बजट के माध्यम से किसानों, युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग की आशाओं पर पानी फेर दिया है।

पायलट ने कहा कि झालावाड़ की स्कूल में हुए हादसे पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और सरकार हफलनामे के माध्यम से यह स्वीकार भी किया था कि प्रदेश की स्कूलों की मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ रूपयों की आवश्यकता है। बावजूद

■ **सचिन पायलट ने कहा कि “पहले केन्द्रीय बजट में राजस्थान की अनदेखी हुई, अब राज्य सरकार ने भी लोगों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है।”**

■ **पायलट ने कहा कि “हाईकोर्ट में सरकार ने हफलनामे के माध्यम से स्वीकार किया था कि प्रदेश की स्कूलों की मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन बजट में मात्र 500 करोड़ रु. का प्रावधान दिखाता है कि सरकार को विद्यार्थियों की सुरक्षा की चिंता नहीं है।”**

इसके राज्य बजट में मात्र 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना यह बताता है कि राज्य सरकार को विद्यार्थियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने बच्चों के भविष्य को अंधेरे में ढकेलने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबन्धन के चलते राजस्व घाटा बढ़ा है, सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। सरकार ने शब्दों के मायाजाल से अपनी 2 वर्षों की नاکामी को छुपाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के ग्त वर्षों के बजट की भांति यह बजट भी धरातल पर उतरने वाला नहीं है।

पायलट ने कहा कि हाई टेक सिटी, आईटी सिटी और एगरो सिटी जैसी बड़ी घोषणाएं धरातल के बजाय केवल

कामजों तक सीमित रह गई है। सरकार अपने पिछले बजट्स की उपलब्धियों पर पूरी तरह मौन साधे हुए है। प्रदेश में बेरोजगारी की भयावह स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का 4 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा नहीं होना और निजी क्षेत्र के रोजगार आंकड़ों का सार्वजनिक न करना सरकार की विफलता को दर्शाता है। पायलट ने कहा कि नहरी क्षेत्रों में फार्म पौड का सन्निघ्डी दो साल से बंद पड़ी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी न करना प्रदेश की गरीब जनता के साथ सीधा अन्याय है। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल उद्योग पर अमेरिकी टैरिफ के संभावित संकट और सोलर पार्कों के नाम पर राज्यवृक्ष खेजड़ी के संरक्षण को लेकर सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है।

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर । नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार के तीसरे बजट को पूरी तरह नीरस और निराशाजनक करार देते हुए कहा कि सरकार घोषणाओं तक सीमित है, जमीनी क्रियान्वयन बेहद कमजोर है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में सरकार ने 2718 बजट घोषणाएं कीं, जिनमें से केवल 20 प्रतिशत ही पूरी हो पाई हैं। 30 प्रतिशत घोषणाएं अब तक शुरू नहीं हुईं, जबकि 40 प्रतिशत पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 के सपने दिखा रही है, जबकि वर्तमान समस्याओं की सुध लेने को तैयार नहीं है। रिफाइनरी शुरू करने की पूर्व घोषणा का जिम्मा करते हुए उन्होंने कहा कि तय समसीमा बीत जाने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ा।

बजट में मेंटल हेल्थ चेकअप सेंटर की घोषणा पर जूली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार को पहले अपना मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नीतियों से कर्मचारी और आमजन परेशान है। प्रदेश में रोज हादसे हो रहे हैं, जो सिस्टम की लापरवाही और खराब कार्यकर्ताओं के लिए हैं। आंगनवाडी सड़ककर्ताओं के लिए की गई घोषणाओं को भी उन्होंने ‘जादू के पिटारे’ जैसा बताया। जूली ने 4.3



नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली

टिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि सरकार बताए कि ये आंकड़े किस आधार पर तय किए गए हैं। सरकार ने दो वर्षों में ही प्रदेश को भारी कर्ज में डुबो दिया है। 1000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, विभिन्न परियोजनाओं और निवेश के दावों पर भी उन्होंने स्पष्ट जवाब मांगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटोसरा ने भी बजट को इतिहास का सबसे नीरस बजट बताया। उन्होंने कहा कि स्कूल मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ की आवश्यकता के मुकाबले मात्र 550 करोड़ रुपये रखे गए हैं। सड़कों और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भवनों के लिए पूर्व में आवंटित राशि खर्च नहीं होने का आरोप लगाया। पेपर लीक मामले में सरकार की कमजोर पैरवी से आरोपी के छूटने का भी जिक्र किया।

विधानसभा में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का शायराना अंदाज दिखा



स्थापना की जाएगी। यह सुनते ही विधानसभा में ठहाके लगने लगे।

किरोडीलाल ने पर्ची भेजी

बजट भाषण के दौरान मंत्री किरोडीलाल ने कांग्रेस प्रदेशध्यक्ष डोटासरा को पर्ची भेजी। पर्ची पढ़कर डोटासरा मुस्कराए और पर्ची अपनी जेब में रख ली। इसी तरह से एक पर्ची सीएम भजनलाल शर्मा तक भी पहुंची। वे भी पर्ची पढ़कर मुस्करा गए। बजट के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी पर्ची की रही।

“भाषण नहीं, बजट पढ़िए।”

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत राजस्थान टॉप अचीवर्स रहा है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है, बजाओ आप ताली। विपक्ष की ओर से ताली नहीं बजाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि यह अचीवमेंट राजस्थान का है, केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। दीया ने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगाताइ इस दिशा में काम रही है। इस पर डोटासरा ने कहा कि “भाषण नहीं, बजट पढ़िए।”

‘अपनी तरह से जगा हुआ हूं’

बजट भाषण शुरू होने के करीब 14 मिनट बाद कृषि मंत्री किरोडीलाल मीणा सदन में पहुंचे। अचानक डोटासरा ने उनकी तरफ इशारा करके कहा कि कृषि मंत्री सो गए हैं। स्पीकर ने कहा कि आप बैठ जाइए, आपने उन्हें जगा दिया। इस पर किरोड़ी ने कहा कि मैं अपनी तरह से जगा हुआ हूं।

स्कूली बजट पर हंगामा

उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में कहा कि पिछली सरकार ने स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जिससे कई दुर्घायपूर्ण घटनाएं हुईं। मैं स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत के लिए 550 करोड़ रुपए की घोषणा करती हू। इस पर डोटासरा ने कहा कि जर्जर स्कूल और क्लासरूम की मरम्मत के लिए 20 हजार करोड़ की आवश्यकता है, आप क्या दे रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। इस पर सदन में हंगामा हो गया, विपक्षी विधायक शेम-शेम के नारे लगाने लगे।

अशोक गहलोत पर तंज कसा

दीया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा कि “सरकार स्कूली बच्चों को खेल सामग्री और जाड़ई पिटारा देगी। इस पर 323 करोड़ खर्च होंगे। दीया कुमारी ने सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि “हमारा जादुई पिटारा पहले वालों की तरह नहीं है, उन्होंने कहा था कि आगे मांगते-मांगते थक जाओगे, मैं देते-देते नहीं थकूंगा। हमारा जाड़ुई पिटारा बच्चों के विकास के लिए है।”

पतंजलि शहद पर शोध प्रकाशित

हरिद्वार । पतंजलि अपने प्रत्येक उत्पाद में गुणवत्ता, शुद्धता और उपभोक्ता सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस प्रतिबद्धता को एक और सशक्त वैज्ञानिक मान्यता उस समय मिली, जब पतंजलि शहद पर किया गया विस्तृत शोध विश्वव्यापी “एक्सपिरर” प्रकाशन के प्रतिष्ठित रिसर्चर् जर्नल “एलाटाइ फूड रिसर्च” में प्रकाशित हुआ। इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि को कहता है, वही करता है और यह एक शाश्वत सत्य है। पतंजलि का उद्देश्य है इस देश को मिलावट के जहर से बचना और पतंजलि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदा ही समर्पित है। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य उत्पादों को लेकर लंबे समय से वैश्विक मंच पर संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा है, किंतु अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित इस शोध द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि भारत में यह विश्वस्वतरीय अनुसंधान संभव है। भी उपलब्ध न केवल पतंजलि के लिए, बल्कि समूचे भारतीय उद्योग के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि पतंजलि शहद में किसी प्रकार की बाहरी शर्करा, सिंथेटिक सिरप या अवांछित रासायनिक अवशेष नहीं पाए गए हैं। पतंजलि के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अनुराग वार्ण्येय ने कहा कि इस शोध में, पतंजलि शहद के 25 विभिन्न बैचों का उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से व्यापक परीक्षण किया गया।

‘कैंडर घोषणा नहीं होने से सहकारी पैक्स कार्मिक निराश’

जयपुर । ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाईज यूनियन ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रान्तीय महासचिव, सहकारी साख समितियां एम्प्लाइज यूनियन के प्रान्तीय अध्यक्ष राजेश्वर नेता सूरज भान सिंह आम्रेरा ने राज्य सरकार के बजट प्रावधान घोषणाओं को उद्योग कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास ,तकनीकी शिक्षा को समर्पित प्रगतिशील बजट बताया है।

आमेरा ने कृषि बजट में 7.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी, प्रदेश के 35लाख किसानों को 25000 करोड रुपए के ब्याजमुक्त शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण वितरण, फसली ऋण पर 800 करोड रुपए का ब्याज अनुदान , 590 करोड रुपए के अकृषि ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा स्वागत योग्य है। आमेरा ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक कार्मिक के वेतन भुगतान सुरक्षा के लिए बहुप्रतीक्षित कैंडर बनाने की घोषणा नहीं होने से प्रदेश के पैक्स कर्मचारियों की भारी असंतोष व निराशा व्याप्त हुई है।

सार-समाचार विकासोन्मुखी है बजट : गजेन्द्र सिंह



जयपुर/जोधपुर । केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान बजट 2026-27 को दूरदर्शी और विकासोन्मुखी बताते हुए कहा कि यह आमजन के जीवन स्तर में सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार, एंशाई आधारित टैरिफिक सिस्टम और बुनियादी ढांचे के विस्तार को उन्होंने क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने युवाओं को 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण, लखपति दीदी योजना की सीमा बढ़ाने, किसान हितैषी प्रावधानों और यमुना जल परियोजना को गेम-चेंजर बताते हुए विश्वास जताया कि यह बजट विकसित राजस्थान के लक्ष्य को मजबूती देगा।

विकसित राजस्थान का विजन : चतुर्वेदी



राजस्थान 2047 की दिशा में गति देगा। चतुर्वेदी ने बताया कि बजट गरीब, युवा, किसान, नारी, मजदूर और अतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आधारभूत ढांचा, उद्योग वित्सार, कृषि व पशुपालन सशक्तीकरण और निवेश प्रोत्साहन से रोजगार सृजन को बल मिलेगा। बजट के तहत वर्ष 2028-29 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के लिए नई भर्तियां, कौशल विकास और स्टार्टअप प्रोत्साहन, महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के प्रावधान भी शामिल हैं। ग्रीन बजट के माध्यम से सौर, पवन और जल ऊर्जा पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे राजस्थान को ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि यह बजट प्रदेशवासियों की खुशहाली सुनिश्चित करते हुए आत्मनिर्भर एवं विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में मौल का पत्थर साबित होगा।

‘उद्योग, कृषि, शिक्षा व स्वास्थ्य पर फोकस’



जयपुर । पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने राजस्थान बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट विकास और जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उन्होंने कई सविहतिषी, सर्वस्पर्शी एवं सर्वसमावेशी बजट प्रस्तुत कर बजट के माध्यम से किसान, युवा, महिला और मध्यम एवं सभी की आकांक्षाओं को पूर्ण किया है। उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना पर विशेष जोर देकर प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया गया है।

‘व्यापारियों व उद्योगों के लिए नई दिशा’

जयपुर । फैंडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री (फोटो) के कार्यकारी अध्यक्ष तथा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. अरुण अग्रवाल ने राजस्थान सरकार के बजट को व्यापारियों व उद्योगों को नई दिशा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में व्यापारियों के लिए एकल खिड़की प्रणाली, व्यापार प्रोत्साहन नीति, और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनसे व्यापार करना आसान होगा और व्यापारियों को नए अवसर प्राप्त होंगे। बजट में उद्योगों के लिए प्लैटफैट केन्द्री व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र, और विशेष औद्योगिक पार्क जैसी घोषणाएँ की गई हैं। इन घोषणाओं से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पर्यटन स्थलों के विकास व प्रचार, स्थानीय कला-संस्कृति को बढ़ावा देने, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन, किसानों के लिए नई तकनीकों व संसाधनों के प्रावधान सराहनीय है।

‘बजट से हरवर्ग को मिलेगा लाभ’ कुसुम यादव

जयपुर । निवर्तमान महापौर कुसुम यादव ने बताया कि यह बजट विकसित राजस्थान 2047 की आधारशिला रखते हुए उसे मूर्तरूप प्रदान करने वाली एक व्यापक कार्ययोजना है। अंत्योदय के संकल्प के साथ यह बजट समाज के हर स्तंभ युवाओं के सपने, किसानों की खुशहाली, महिलाओं के सम्मान और गरीबों के कल्याण को नई ऊंचाइयां देने के लिए समर्पित है।बजट में आधारभूत ढांचे के विस्तार, ग्रामीण विकास, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देते हुए लखपति दीदी योजना के तहत पात्र महिलाओं को अब ढेढ़ लाख रुपये तक का ऋण देने की बात कही है।

‘विकासोन्मुखी है राजस्थान बजट’



जयपुर । पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठीड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी को राजस्थान बजट 2026-27 प्रस्तुत करने पर शुभकामनाएं देते हुए इसे ऐतिहासिक और विकासोन्मुखी बजट बताया। उन्होंने कहा कि करीब 21.52 लाख करोड़ रुपये के बजट आकार और 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रभावी पूंजीगत व्यय का प्रावधान राज्य की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का संकेत है। किसानों के लिए 1.19 लाख करोड रुपये का कृषि बजट, ब्याज मुक्त कृषि ऋण, 50 हजार सोलर पंप, सिंचाई विस्तार और आधुनिक कृषि योजनाएं आय बढ़ाने में सहायक होंगी। उन्होंने बताया कि ग्रीन बजट के तहत 33 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान, 10 करोड पौधारोपण और अरावली संरक्षण जैसी पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम हैं।

‘अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने वाला बजट’



जयपुर । करधान कॉर्पोरेट विशेषज्ञ सीए अंशुल चितौड़ी एवं उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया

कुमारी द्वारा प्रस्तुत 2026-27 के बजट को राजस्थान की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने वाला दूरदर्शी दस्तावेज बताया। चितौड़ी का कहना है कि बड़े पैमाने पर नई सड़कों का निर्माण न केवल कनेक्टिविटी सुधारेगा, बल्कि निजी निवेश को भी आकर्षित करेगा। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों की घोषणा और मेधावी छात्रों को डिजिटल शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देना मानव संसाधन में किया गया एक बड़ा निवेश है। ऋण दस्तावेजों पर पंजीकरण दर और स्ट्याम्प ड्यूटी में कमी से रियल एस्टेट क्षेत्र में तरलता बढ़ेगी। बकाया करों के लिए एग्मनेस्टी योजना लाना राजस्व वसूली को सरल बनायेगा। अन्य राज्यों के वाहनों पर टैक्स में छूट से उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी।

सर्वांगीण विकास का बजट : गोतोड़



प्रदेश की अर्थव्यवस्था 21 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंचने और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का अनुमान सरकार की मजबूत वित्तीय दिशा को दर्शाता है। युवाओं के लिए राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण, 30 हजार युवाओं को लाभ और 30 करोड़ रुपये से एंशाई टेक्नो हब की स्थापना जैसे प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की ऋण सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये करना, रूरल वूमेन बीपीओ और राजसूबी स्टोर खोलने की घोषणा को उन्होंने सशक्त कदम बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को मजबूती देगा।

‘उद्योग-व्यापार को गति देगा बजट’



2026-27 को उद्योग व व्यापार को गति देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को ऋण-सुविधा के लिए 15 करोड़ की मार्जिन मनी उपलब्ध कराने का प्रावधान-जिससे नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि उद्यमियों को पूंजी की कमी के कारण अवसर न छूटें, और वित्तीय सहायता गेम-चेंजर साबित हो। साथ ही बड़े औद्योगिक क्षेत्र के लिए 3600 हेक्टेयर भूमि का विकास और अगले दो वर्षों में 600 करोड़ खर्च का प्रस्ताव तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 400 करोड़ का प्रावधान अहम है। डिजिटल और सेवाओं का सरलीकरण और ई-मित्र की 100 महत्वपूर्ण सेवाएं वाटरपए प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने से राहत मिलेगी।

‘पर्यटन ढांचे को मिलेगी मजबूती’



जयपुर । इंडियन हैरिटेज होटल्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल, गज सिंह अलसीसर ने कहा कि राजस्थान के बजट में शेखावाटी क्षेत्र में धरोहर संरक्षण, जैसलमेर में विशेष पर्यटन क्षेत्र का विकास, थार सांस्कृतिक सर्किट तथा भरतपुर में ब्रज कन्वेंशन सेंटर की स्थापना से राज्य के पर्यटन ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। झुंझुनूं, चूरू और सीकर की 660 से अधिक हवेलियों के संरक्षण, फेसाड शुधार, हेरिटेज स्ट्रीट फर्नीचर के विकास के लिए आगामी दो वर्षों में 200 करोड़ रुपये का व्यय ऐतिहासिक विरासत को नई पहचान देगा।

वहीं, हवेलियों को पर्यटन इकाई में बदलने पर वित्तीय सहायता से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। शेखावाटी की हवेलियों को यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में शामिल कराने का प्रयास प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय पहचान बढ़ाएगा।